माकपा का प्रेस वक्तव्य
रांची, 11 फरवरी, 2022
हेमंत सरकार स्थानीयता को परिभाषित कर नियोजन नीति की घोषणा जल्द करे साथ ही
भाषा पर जारी 27 दिसंबर 2021 के झारखंड गजट को स्थगित कर इस पर चर्चा के लिए अविलंब सर्वदलीय बैठक बुलाए - माकपा

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का राज्य सचिवमंडल हेमंत सरकार से मांग करता है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के संबंध मे राज्यपाल के आदेश से जारी दिनांक 27 दिसंबर के झारखंड गजट (असाधारण) की को तत्काल स्थगित रख कर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अविलंब सर्वदलीय बैठक बुलाए.
झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित इस अधिसूचना से राज्य मे भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है और कुछ संगठनों द्वारा भाषा के नाम पर गैर जिम्मेदाराना बयान देकर राज्य की जनता को विभाजित किए जाने का काम प्रारंभ कर दिया है. हेमंत सरकार ने भी अलोकतांत्रिक तरीके से इस मुद्दे पर झारखंड के राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से बिना व्यापक चर्चा किए इसे जल्दबाजी मे गजट कर दिया जिससे भाषा के सवाल पर राज्य की जनता के बीच विभाजन पैदा करने वाले तत्वों को मौका मिल गया. क्योंकि राज्य के लाखों बेरोजगार युवा रोजगार नहीं मिलने की वजह से अपने भविष्य की चिंता के कारण आक्रोशित हैं और विभाजनकारी ताकतें इसका फायदा उठाने की ताक में हैं.
माकपा शुरू से भाषा के आधार पर राज्य गठन किए जाने की पक्षधर रही है. झारखंड मे भी माकपा नौकरी समेत राजकीय प्रयोजनो के लिए जो सात सूत्री दिशा निर्देश है जिसपर वर्ष 2007 मे झारखंड सरकार ने अधिसूचना भी जारी किया है लेकिन इसे झारखंड मे सही तौर पर लागू नहीं किया गया. माकपा की यह स्पष्ट समझ है कि झारखंड की आदिवासी भाषाओं समेत यहां की मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षण दिए जाने के साथ - साथ इन भाषाओं की पढ़ाई प्राईमरी कक्षा से करने तथा जिस इलाके मे यह अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है वहां इस भाषा के जानकार कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग करती रही है लेकिन भाषा के आधार पर यहां के लोगों के बीच विभाजनकारी गतिविधियों का पार्टी विरोध करती है.
इस पृष्ठभूमि मे माकपा का राज्य सचिवमंडल हेमंत सरकार से मांग करता है कि भाषा के संबंध मे जारी झारखंड गजट को तत्काल स्थगित रख कर इस पर चर्चा के लिए अविलंब सर्वदलीय बैठक बुलाए ताकि राज्य के हित मे इस मुद्दे पर एक सर्वमान्य हल निकाला जा सके. माकपा राज्य सरकार से यह भी मांग करती है कि झारखंड मे स्थानीयता को जल्द परिभाषित कर राज्य के लिए एक नियोजन नीति तय करे.

प्रकाश विप्लव
राज्य सचिव